राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 785/2024

धर्मेन्द आर्य —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उपायुक्त एवं उप सचिव–II, ग्रामीण पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सीकर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पूनियां, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ग्राम सेवक के पद पर दिनांक 01.09.1986 को हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति पलसाना, जिला सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.08.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति अजीतगढ़, सीकर से जिला परिषद् झुंझुंनू में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.07.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला परिषद् झुंझुंनू से पंचायत समिति संगरिया, जिला हनुमानगढ़ में कर दिया गया, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 04.09.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पंचायत समिति देलवाड़ा, जिला राजसमंद में मात्र साढ़े चार माह की अल्पावधि में बिना किसी प्रशासनिक

आवश्यकता के 600 कि.मी. दूर किया गया है। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 205/2021 रामनिवास यादव बनाम राजस्थान राज्य में निर्णय दिनांक 19.01.2021 एवं माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 376/2024 कैलाश गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य में निर्णय दिनांक 23.02.2024 का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी समान बताया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यरत रखे जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति ग्राम सेवक के पद पर दिनांक 01.09.1986 को हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति पलसाना, जिला सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पंचायत समिति देलवाड़ा, जिला राजसमंद में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

5. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 600 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276)** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।
7. आदेश आज दिनांक ..... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)